1.00 P.M

नीतियां पांव पसारते पसारते अब पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक उपक्रमों का सर्वनाश करने तक जा पहुंची हैं । पिछले 25 वर्षों में जहां मजदूरों ने धीरे धीरे अपने अधिकारों को संचित किया था, आज उनके उन अधिकारों का हनन हो रहा है । केन्द्र सरकार के हमले तो तमाम क्षेत्रों में हो ही रहे हैं किन्तु सार्वजनिक उपक्रमों को तो इस तरह नेस्तनाबूद करने की मुहीम सी चलाई जा रही है । फलतः सिर्फ मजदूरों, कर्मचारियों के घर ही नहीं बरबाद हो रहे हैं अपितु उन पर आश्रित छोटे छोटे हाट बाजारों में चीज़ें बेच गुजर बसर करने वालों का संसार भी उजड़ता जा रहा है । महोदय, हमारा संविधान हर मनुष्य को जीने का अधिकार देता है किन्तु बिना वेतन के मजदूर उसी तरह आत्महत्या करने के लिए मजबूर किये जा रहे हैं जैसा कुछ दिन पहले देश के कई भागों के किसानों के साथ हुआ था । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन है ? क्या इसे सीधे सीधे मानवाधिकारों का हनन नहीं कहना चाहिये ? पैसों के अभाव में मजदूरों के लिए दो वक्त की रोटी मुहाल हो गई है । बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देनी पड़ी है । नादान शिशु इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं । इस स्थिति में इन असहाय मजदूर कर्मचारियों की मदद नितांत मानवीय मांग है । अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि कुछ जिम्मेदार मंत्रियों को ले कर एक कमेटी तत्काल बनाई जाए जो इनकी समस्याओं का समुचित समाधान पेश कर सके तथा उनके बकाया वेतन और मजदूरी आदि की तहकीकात कर सके । वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान चाहूंगी । वित्त मंत्री महोदय शीघ्र इन संस्थानों के मजदूरों, कर्मचारियों के बकाया वेतन के निपटान संबंधी निर्देश दें जिससे मौत के कगार पर खड़े हज़ारों परिवारों को अकाल मृत्यु का शिकार बनने से बचाया जा सके । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश): मैं इसके साथ एसोसिएट करता हूं।

SHRI V.P. DURAISAMY(Tamil Nadu): Sir, I associate myself with it.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU(Pondicherry): Sir, I associate myself with it.

MR. CHAIRMAN: All right. Now it is one o'clock. We will continue till the Special Mentions are over. Shri R.P. Goenka.

Hike in International oil Price

SHRI R.P. GOENKA (RAJASTHAN): Sir, last week, the international prices of oil crossed $32 a barrel. It will have its widespread ramifications in our country. Therefore, it is important for us to take immediate action so as to prevent problems from blowing up further. The hike in oil prices will have three consequences. First, the deficit in balance of payments will expand by about five billion dollars. Secondly, the Oil Pool deficit will increase to Rs.20,000 crores. Thirdly, the Oil Pool deficit, if financed from

bank credit, will divert funds from productive to non-productive users, thereby putting pressure on the rate of interest. It is, therefore, essential that urgent measures are initiated to meet the balance of payments deficit either from current foreign exchange earnings like exports, or from external sources like FII investment, or from borrowings; otherwise, the rupee will fall much further, creating additional problems.

Alternatively, the RBI will have to bring down the foreign exchange reserves to the extent of five billion dollars. Both the situations are undesirable. In any case, it would not be possible for us to carry on with the subsidies on petroleum products any further. The Government will have to raise the prices of petroleum products to bring down the Oil Pool deficit. Will the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas clarify: (a) what steps are being taken to increase the domestic production of oil; (b) how the additional deficit in balance of payments will be funded; (c) whether domestic prices of petroleum products like LPG, diesel, kerosene oil, etc. will be increased in the near future and (d) how these measures will affect the inflation within the country? Thank you.

Pitiable Condition of Potato and Sugarcane Growers

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय। यह वेजीटेरियन सवाल है।

उत्तर प्रदेश के किसानों, खास तौर पर पश्चिमी इलाके के, जहां पर आलू और गन्ने की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, उनकी स्थिति दयनीय है। एक बोरी आलू में 80 से 85 किलो तक आता है। कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है जिसका किराया 65 रुपया प्रति बोरी है। बोरियों को वहां से निकालने पर मण्डी ले जाने का व्यय 20 रुपए का है। सफाई और पल्लेदारी, आढ़त आदि में प्रति बोरी 20 रुपए खर्च आता है। जिस समय आलू खेत से निकाला गया उस समय खेत पर ही आलू की कीमत 130 रुपए प्रति बोरी थी। आज आलू की कीमत प्रति बोरी 100 रुपए भी मुश्किल से मिल रही है। खाली बोरियों का दाम 20 से 25 रुपए तक है। किसानों को लागत मूल्य क्या मिलता है, उल्टे घाटा हो रहा है। आश्चर्य है कि मात्र 50 से 70 किलो मीटर की दूरी पर दिल्ली पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जहां खुदरा आलू की बिक्री दिल्ली में 10 से 12 रुपए प्रति किलो है परंतु न तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और न दिल्ली की केन्द्र सरकार किसानों की इस दुखद स्थिति पर कोई विचार कर रही है। अगर सरकार अपनी एजेंसी से 5 रुपए किलो भी किसानों का आलू खरीद ले और दिल्ली लाकर 6 या 7 रुपए किलो भी बेचे तो कम से कम एक रुपए प्रति किलो सरकार को मुनाफा होगा और किसानों को भी लागत से अधिक मूल्य मिलेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार से किसानों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने एवं उनको उबारने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। इसी प्रकार से पूर्वांचल के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज तक उनके गन्ने के बकाया दामों को नहीं दिया गया है। अभी मेरे पास किसानों का एक शिष्ट मंडल आया और मिला। उनकी व्यथा को सुनकर मन में पीड़ा हो रही